युवा और अधेड़ उम्र के मतदाताओं में एनडीए और महागठबंधन के बीच नजदीकी मुकाबला है, पर बुजुर्गों में एनडीए की बड़ी बढ़त है.

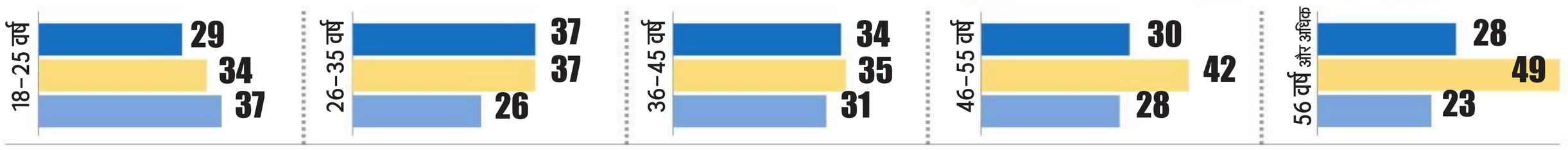

एनडीए को बढ़त, पर आसान नहीं है डगर

विशेषज्ञ

सुहास पलशीकर,
मुख्य संपादक, स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स एवं सह-निदेशक, लोकनीति

संदीप शास्त्री,
उपकुलपति, जैन विश्वविद्यालय

संजय कुमार,
प्रोफेसर एवं सह-निदेशक, लोकनीति

बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई निश्चित रूप से जटिल है और लोकनीति-सीएसडीएस का चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण में इसके कई संकेत हैं. एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में मतदाताओं का भरोसा बरकरार है. यह भी कि लोजपा के राज्य स्तर पर एनडीए से अलग होने से भाजपा-जदयू गठबंधन की मुश्किलें बढ़ी हैं. पर लालू परिवार का युवा उत्तराधिकारी मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है.

एनडीए में कुछ विरोधाभास उभरता हुआ भी दिख रहा है. जदयू समर्थक अपने मुख्यमंत्री का जोरदार समर्थन कर रहे हैं, पर भाजपा के मतदाता उनके नेतृत्व को लेकर उतने उत्साहित नहीं दिख रहे हैं. यदि यह रूझान बना रहता है, तो एनडीए इस चुनाव में केंद्र सरकार की लोकप्रियता की वजह से आगे रहेगा और अपनी शंकाओं के बावजूद भाजपा समर्थक गठबंधन के उमीदवार को वोट देंगे.

जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, दो बातें देखने लायक होंगी. प्रधानमंत्री मोदी की 12 रैलियां कैसे एनडीए के लिए अधिक समर्थन जुटाती हैं? दूसरी बात, क्या तेजस्वी यादव अपने समर्थन को राजद के परंपरागत आधार से आगे बढ़ा सकेंगे? लोकनीति-सीएसडीएस सर्वेक्षण इंगित करता है कि लालू यादव के इस चयनित उत्तराधिकारी की लोकप्रियता बढ़ी है. बहुत कुछ उन मतदाताओं के रवैये पर निर्भर करेगा, जिन्होंने अभी तक अपना रुख तय नहीं किया है.

लोजपा के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें है. सर्वेक्षण इंगित करता है कि उच्च जातियों में पार्टी की कुछ पैठ बन रही है, खासकर उन सीटों पर, जहां जदयू मैदान में है. यह भी अहम है कि पासवान वोट किधर का रुख करता है. चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण में दिखता है कि जहां भाजपा लड़ रही है, वहां इसका रुख भाजपा की ओर है तथा जहां जदयू का उम्मीदवार है, वहां यह महागठबंधन और लोजपा में बंट रहा है.

महागठबंधन की अपनी चुनौतियां हैं. राजद अपने परंपरागत वोट को बरकरार रख सका है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने परंपरागत आधार का पूरा समर्थन इस गठबंधन के पीछे लामबंद कर पा रही है. उसके आधे से भी कम परंपरागत मतदाता महागठबंधन के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध हैं. दो अन्य गठबंधनों का बनना, खासकर एमआइएम का मैदान में आना- एक इस चुनाव का एक बड़ा कारक है और इससे महागठबंधन को अधिक नुकसान होने की आशंका है.

सभी की निगाहें हालांकि जातिगत समीकरण पर है, इस सर्वेक्षण में 18 से 25 साल आयु के युवा नीतीश सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं. उनकी पसंद तीन हिस्सों में बंटी दिखती है और सबसे बड़ा हिस्सा छोटी पार्टियों या रालोसपा-बसपा-एमआइएम के साथ है. इस आयु वर्ग की दूसरी पसंद तेजस्वी यादव के नेतृत्ववाला गठबंधन है और सबसे अंत में एनडीए इनकी पसंद है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस आयु वर्ग ने बिहार में एनडीए को जोरदार समर्थन दिया था.

महिलाओं का मुख्य रूझान एनडीए की ओर है. ऐसा युवा महिलाओं में भी है. इस वर्ग में एनडीए और महागठबंधन के बीच अधिक अंतर स्नातकों की तुलना में उन महिलाओं में है, जिन्होंने उच्च शिक्षा नहीं हासिल की है. हालांकि उच्च जातियों तथा मध्य और निम्न अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिक समर्थन एनडीए को है, पर उन्हें यह शिकायत भी है कि नीतीश सरकार ने उनके हितों के लिए समुचित काम नहीं किया है. यादव वोट मजबूती से महागठबंधन के साथ है, पर मुस्लिम मतों में महागठबंधन और छोटी पार्टियों के बीच विभाजन है.

हालांकि महागठबंधन अपने पीछे गरीबों को बड़ी तादाद में अपने पीछे लामबंद करने में कामयाब नहीं रहा है, चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण का एक अहम निष्कर्ष यह है कि मध्य और उच्च आय वर्ग के मतदाता महागठबंधन की अपेक्षा एनडीए को अधिक पसंद कर रहे हैं. यदि महागठबंधन कुछ हद तक अदृश्य इस वर्ग विभाजन को रेखांकित कर पाता है, तो एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती है.

दोनों गठबंधनों में जोरदार टक्कर

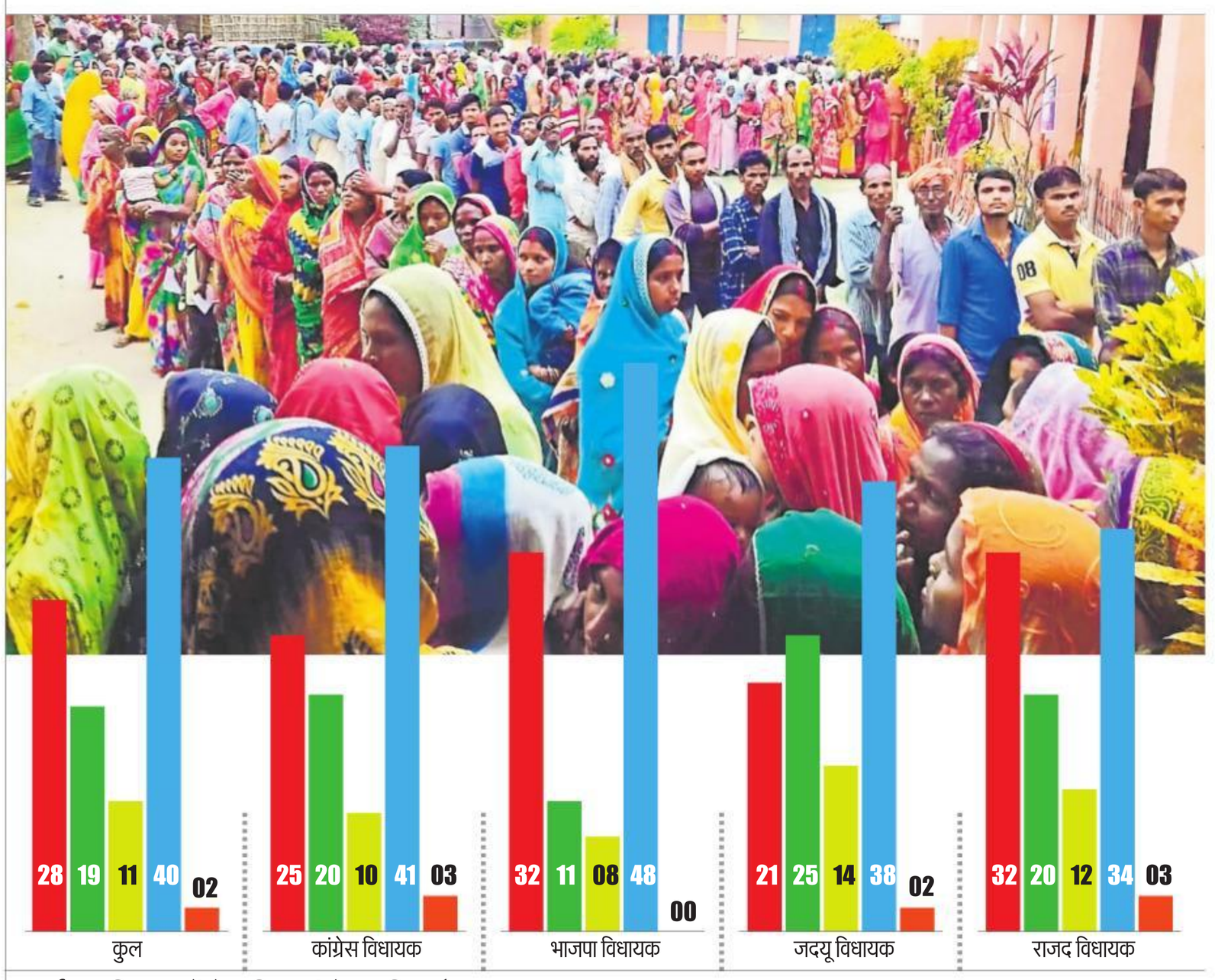

वर्तमान विधायकों के प्रति असंतोष अधिक है. नोट : सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं और पूर्ण संख्या करने के कारण उनका योग 100 नहीं हो सकता है.

पूर्ण संतुष्ट | किंचित संतुष्ट | किंचित असंतुष्ट | पूर्ण असंतुष्ट | कोई उत्तर नहीं

पूछा गया प्रश्न : क्या आप अपने विधायक के पांच वर्षों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं?

शिक्षितों में दोनों पक्षों के बीच नजदीकी मुकाबला

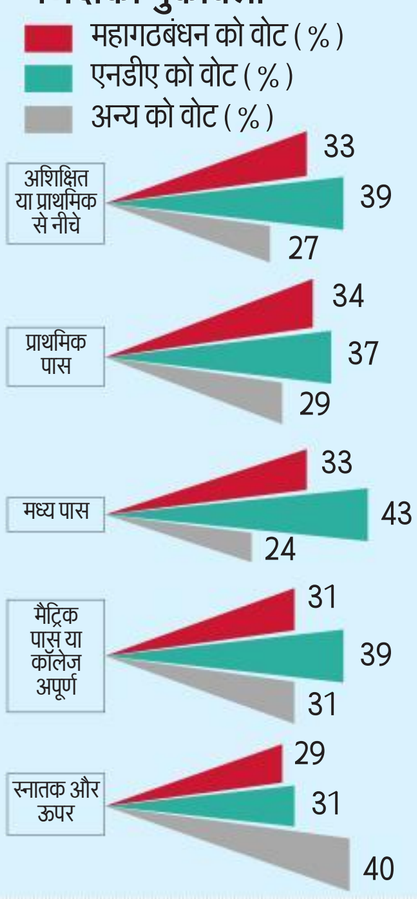

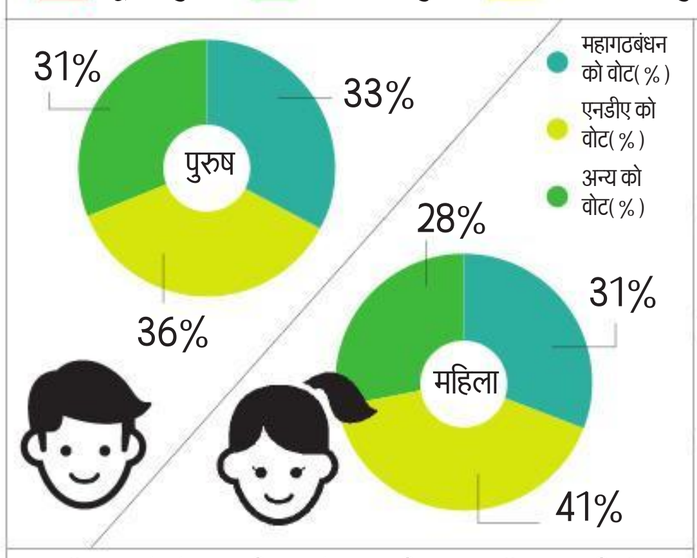

महिलाओं में एनडीए को अच्छी बढ़त दिख रही है.

आय वर्ग में मतों के रूझान

● मासिक पारिवारिक आय (रुपये में)

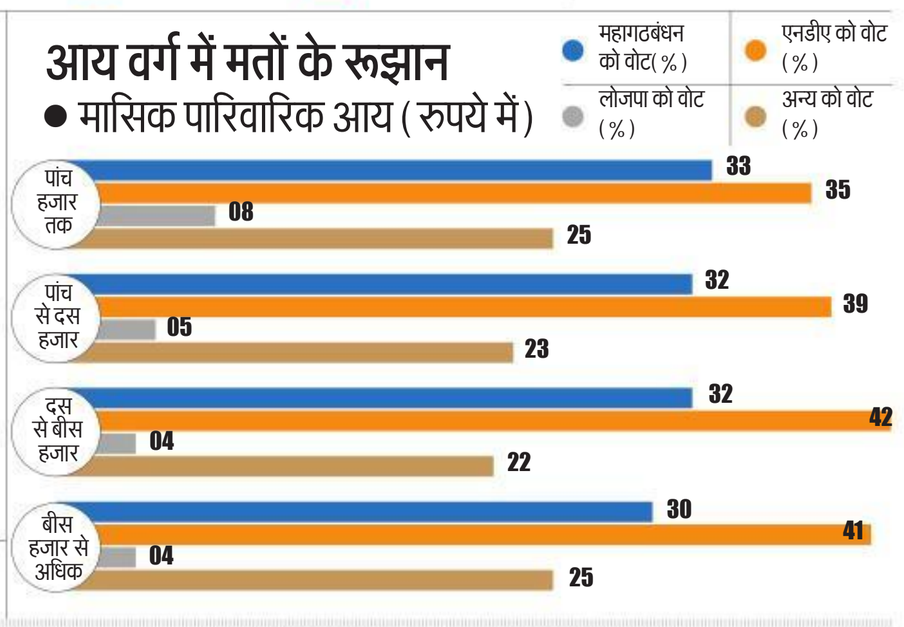

बिहार में चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण चुनौतीपूर्ण

संजय कुमार, प्रोफेसर, सीएसडीएस

वैसे तो किसी भी राज्य में चुनाव से पहले सर्वेक्षण करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अन्य कई राज्यों की तुलना में बिहार में यह करना बहुत ही अधिक कठिन है. ऐसा इसलिए नहीं है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से अधिक मताग्रही और सचेत होते हैं, इस कारण उनके मतदान की पसंद जान पाना मुश्किल है. सर्वेक्षण अधिक संख्या में राजनीतिक दलों के होने, गठबंधनों के सहयोगियों के बदलने और बहुपक्षीय मुकाबला होने के कारण एक कठिन काम हो जाता है. बड़ी तादाद में जातियों के होने तथा जातिगत आधार पर मतदान के ठोस रूझान की वजह से स्थिति और भी जटिल हो जाती है. पर सबसे बड़ी चुनौती चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की है.

मतदाताओं और पार्टियों की बहुलता को देखते हुए हमने सीटों के आकलन का हिसाब एक विशेष प्रोग्राम के इस्तेमाल से किया, जिसे 'स्विंग मॉडल' कहा जाता है. यह किसी पार्टी या गठबंधन के पक्ष या विपक्ष में मतदाताओं के बदलते रूझान पर आधारित होता है. इसमें पिछले चुनाव के मतदान को आधार बनाकर चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण के आंकड़ों को देखा जाता है. यदि किसी पक्ष में रूझान सकारात्मक है, तो उसके अधिक सीटें जीतने की उम्मीद होती है तथा रूझान नकारात्मक होने की स्थिति में सीटों के नुकसान की आशंका रहती है. वर्ष 2015 के गठबंधनों का हिसाब इस बार बहुत हद तक बदल गया है, सो 2015 को आधार बनाकर 2020 में आकलन कर पाना बहुत जटिल है. पार्टियों के भीतर टूट से भी चुनौती बढ़ जाती है क्योंकि गुटों के आधार पर पिछले चुनाव के वोटों का हिसाब लगाना कठिन हो जाता है. बिहार में यह चुनौती कम है क्योंकि वहां पार्टियों में टूट बहुत कम होती है. दो या अधिक दलों का विलय से भी ऐसी ही मुश्किल खड़ी होती है.

हमारे मेथड या तरीके इन चुनौतियों के समाधान के लिए ही होते हैं. पर मुश्किल यह भी है कि लोग चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण से यह जानने में अधिक दिलचस्पी दिखाते हैं कि आखिरकार हार-जीत तथा सीटों का हिसाब क्या है. उल्लेखनीय है कि ऐसे सर्वेक्षण उस समय लोगों की पसंद को ही जाहिर करते हैं. प्रचार की अपनी प्रभावी भूमिका होती है तथा पार्टियां और उम्मीदवार अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं. इससे लोगों की पसंद बदलती भी है. ऐसे में चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण से मतदान के दिन की सटीक भविष्यवाणी की अपेक्षा करना तार्किक नहीं है. इसे एक उदाहरण से समझते हैं. हम कार से कहीं जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक निर्धारित समय में हम उस जगह पहुंच जायेंगे. लेकिन अगर रास्ते में यातायात बाधित हो या हम किसी से मिलने या खाने-पीने के लिए कहीं रुक जाते हैं, तो हमारा अनुमानित समय बदल जायेगा. इसी तरह से चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण से सही या करीबी भविष्यवाणी करना तभी संभव है, जब स्थितियां सर्वेक्षण के समय के समान ही बनी रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है. हमारे हालिया सर्वेक्षण में एनडीए के लिए 38, राजद गठबंधन के लिए 32, रालोसपा गठबंधन के लिए सात, लोजपा के लिए छह तथा अन्य छोटी पार्टियों और निर्दलियों के लिए 17 प्रतिशत मतों का आकलन है. इस आकलन के आधार पर हमने एनडीए के लिए 133-143, राजद गठबंधन के लिए 88-98, लोजपा के लिए 2-6 तथा अन्य के खाते में 6-10 सीटों का अनुमान लगाया है. यह अनुमान 10 से 17 अक्टूबर के बीच सर्वेक्षण में मतदाताओं के मन के आधार पर आकलित किया गया है और इससे 10 नवंबर के परिणाम के बारे में भविष्यवाणी करने में हमें मदद नहीं मिल सकती है. मतदान अनेक चरणों में होंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने पाना प्रचार अभियान अभी शुरू ही किया है. उनके प्रचार का मतदाताओं पर असर पड़ सकता है, जैसा कि अन्य राज्यों में पिछले कुछ सालों में देखा गया है.

कोई भी चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण रैलियों और प्रचार के असर का आकलन नहीं कर सकता है. उस असर को ऐसे सर्वेक्षण से जोड़ना इसके साथ न्याय नहीं होगा. एक समस्या यह भी है कि मीडिया और एजेंसियां ऐसे सर्वेक्षणों को एकमात्र सत्य और अंतिम परिणाम की तरह प्रस्तुत करते हैं. तो, केवल लोगों को ही दोष नहीं दिया जा सकता है, मीडिया और एजेंसियों को भी चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण से ऐसी अतार्किक अपेक्षा का दोष लेना होगा. कोरोना माहमारी की वजह से सावधानी और दूरी बरतने की मजबूरी तथा दूर-दूर तक यात्रा नहीं कर पाने की मुश्किल ने भी इस सर्वेक्षण को चुनौतीपूर्ण बना दिया. कई जगहों पर हमें स्थानीय सर्वेक्षकों की सहायता लेनी पड़ी. मुझे उम्मीद है कि यह समस्या एक विशेष परिस्थिति है और जल्दी ही इससे छुटकारा मिल जायेगा.